

सिटी आस-पास संदेश

खबर संक्षेप

निरोगी काया के लिए संयमित दिनचर्या जरूरी

बाबूगंज। निरोगी काया के लिए सभी के लिए हरि धैत्य टीकरामाई ने रुदापुर में अस्पताल के लोकार्पण के अवसर पर कहा की। उहोंने कहा वारे व्यक्तियों की दिनचर्या सुधार से लेकर शर्त तक अनियमित होती जा रही है। खान-पान से लेकर रात सोने की दिनचर्या में परिवर्तन के कारण को आहार करने में कई परायी की व्याधियां उपलब्ध हो रही हैं। जिसके लिए सभी को अपनी दिनचर्या में सुधार, संतुलित आहार करने स्वस्थ जीवन जीना सकते हैं। क्षेत्रीय विद्यायक प्रवीण पटेल ने कहा शिक्षा के साथ सभी को अनियमित रूप से स्वस्थ व्याधियां की महापर्पण जानकारी होना जरूरी है। स्वयं के स्वच्छता, आहार एवं विचार से ही मानव जीवन स्वस्थ्य के प्रति संवेदन रहकर लाभी आयु जी सकते हैं।

अस्पताल के आयोजिक जीं रिचा तिवारी ने मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों का स्वाचार एवं अधिनेनद किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

धान की तकाल खरीद हो नहीं तो अधिकारियों के आवास पर होगा प्रदर्शन : रेवती रमण

अखंड भारत संदेश

करछना आदर्श विधानसभा सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध-रेवती रमण सिंहकरछना में 5.98 करोड़ सांसद निधि से 50 सड़क का लोकार्पण



पचास सड़कों का लोकार्पण करते हुए कुरवर रेवती रमण सिंह।

करछना। राज्य सभा सांसद कुरवर रेवती रमण सिंह ने करछना विधानसभा में 5.98 करोड़ से 50 सड़कों का लोकार्पण करते हुए कहा कि करछना को आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित करना ही दमारी पल्ली प्राथमिकता रही है जो लगभग पूरा हुआ यहाँ सड़कों का जाल बिछाया गया जनपद में सबसे ज्यादा सरकारी ट्रॉफेरल भी करछना में है जिलाली लगभग सभी मजरे पुरवे में है। यहां लगभग सभी आवासभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं सांसद ने कहा कि करछना विधानसभा में ही इंट्रोटेट टाउनशिप में विश्वविद्यालय की तरह एक मेंदाता या अपेलों जैसा विश्वविद्यालय अस्पताल अखिल भारतीय सरकार बनने के बाद खुलवाया जायेगा जिससे प्रवायगराज सहित मध्यप्रदेश के क्षेत्राभासियों को लाभ होगा साथ में कर्ची में अधिविहित जीवन पर स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए फैक्टरी का निर्माण कराया जायेगा और यह तभी सम्भव है जब 2022

में अखिलेश सरकार बनें क्योंकि भाजपा को गरीबों के दुखदंड से कुछ लेना देना नहीं है।

जिसपर सांसद ने अधिकारियों से बातों कर गरीबों के दुखदंड से कुछ लेना देना नहीं है।

चेतावा कि धान की खेती तकाल चालू सांसद से किसानों ने शिकायत किया कि

किया जाय नहीं तो इस बार तहसील की धान की सरकारी खरीद नहीं हो रही है।

जगह अधिकारियों का आवास घेरने का यादव आदि रहे।

पुलिस के हत्थे छढ़े भैस घोर, बम के साथ दो को भेजा जेल

करछना। इन दिनों चलाये जा रहे धर

पकड़ अधिनायक के छहत भारतीयों को उपर पालने के ऊपर नारजीगी

जाते हैं तो वह ग्राम प्रधानों के ऊपर निर्विवाद देने का कार्य करते हैं।

जिसका जीता जायाता उदाहण ग्राम पंचायत को नियमन का कोटेदार है, जिसके विरुद्ध गार्वावाही अंतर्गत लोप्ता ग्राम पंचायत को नियमन का कोटेदार है, जिसके विरुद्ध से उप जिलाधिकारी को रोकने का नियमन बनाया गया है और जीता तरह सांसद को दुखाने का ताक देने का कार्य करते हैं। और जीता तरह उत्तर विक्रेता अल्हवा द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने पर उप जिला अधिकारी को गोपनीय वार्ता को भरकर प्रायस निरंतर जारी है। प्रधान ने प्रमुख संचिव खाड़ी एवं आपूर्ति लखनऊ से लिखित शिकायत उप जि�लाधिकारी और आपूर्ति विभाग से की जाती है तो वह ग्राम प्रधानों के ऊपर नारजीगी जाते हैं तो उन्हें उत्तर विक्रेता द्वारा ग्राम प्रधानों को जो पंचायतीराज अधिनियम में नियम प्रदत्त अधिकार कर लाने पर उसमें किसी अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा हनन न किया जाए तो वह विक्रेता अधिकारियों के विरुद्ध संघर्ष करता है। जिसके अधिकारी द्वारा हनन न किया जाए तो वह विभागों के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है।

जिसका कारण गांवों में सर्वजनिक जीवनों का जारी है। कई ग्राम प्रधानों ने इस आशय को शिकायत कर दी है। जिससे दर विक्रेता अधिकारी के अनुरूप नहीं चल रही है। जिससे

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

ज्ञान पौंपते प्रधान संघ कोरांव के ग्राम प्रधान

पंचायतों में सर्वजनिक जीवनों भी अतिरिक्त जीवनों में संबंधित होते हैं।

सम्पादकीय

क्यों डरती है सरकार

पिछले एक साल से जिन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, उन तीनों कानूनों को चंद मिनटों में मोदी सरकार ने संसद में रद्द करवा दिया। आप चाहें तो इसे बहुमत की ताकत कह सकते हैं, आप चाहें तो इसमें लोकतंत्र का मखौल उड़ा देख सकते हैं। ये सही है कि किसान लगातार कानूनों को रद्द करने की ही मांग पर अडे थे, उन्हें कानूनों में न संशोधन मंजूर था, न कुछ समय का स्थगन। किसान इन कानूनों को चाहते ही नहीं थे, इसलिए उनके आंदोलन का यह उद्देश्य साफ था कि जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। और अब मोदी सरकार यही उम्मीद कर रही है कि हमने कानून वापस ले लिया है, तो अब किसानों को भी घर लौट जाना चाहिए। हालांकि किसानों के आंदोलन में कानून वापसी के साथ और कई दूसरी मार्गें भी थीं, जिनकी सरकार उपेक्षा कर रही है। इसलिए अपनी उम्मीदों के पूरे न होने का दोष किसानों पर नहीं मढ़ा जा सकता। यह सभी को ज्ञात है कि कृषि विधेयकों को किस तरह हड्डबड़ी में सरकार ने संसद से पारित करवा कर कानून बनवाया था। इसके लिए न कृषि अर्थशास्त्रियों से सरकार ने चर्चा की, न किसान संगठनों से रायशुमारी की। किसानों ने कभी ऐसे कानूनों की मांग नहीं की थी, लेकिन उन्हें जबरन थोपकर सरकार यही साबित करने पर तुली थी कि इससे किसानों का भला होगा। हालांकि इस दौरान उद्योगपतियों का कितना भला होता, यह सबको पता चल गया था। किसान सड़क पर मोर्चा खोलकर बैठे रहे, इस दौरान दिल्ली में कई बरसों बाद कड़कड़ातीमात्रा सर्दी पड़ी, सर्दी के साथ भारी बारिश और हवाओं की मार खुलेखुला आसमान के नीचे रह रहे किसानों ने खाई, फिर तपती गर्मी, लू, कोरोना और प्रदूषण सारी मुश्किलें किसानों ने सहीं। लेकिन सरकार ने उनसे बातचीत के रास्ते बंद रखे।

बल्कि मत्रियों की टोली देश भर में धूम कर प्रेस कांफ्रेस कर कृषि कानूनों के फायदे गिनाते रही। 70 सालों में कई तरह के मिजाज वाली सरकारें देश ने देखी हैं, लेकिन ऐसी अड़ियल और सवैदनहीन सरकार पहले कभी देश में नहीं रही। अब भी कृषि कानून वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री ने एक तरह से किसानों पर तंज ही कसा कि वे दीए के प्रकाश जैसा सत्य नहीं समझ पाए। संसद में कृषि कानून निरसन विधेयक पेश करने से पहले कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सांसदों को जो नोट भेजा, उसमें लिखा है कि इन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 'किसानों का केवल एक छोटा सा समूह ही विरोध कर रहा है, समावेशी विकास के लिए सभी को साथ लेकर चलना समय की मांग है। इस नोट में एक बार फिर कृषि कानूनों से किसानों को होने वाले संभावित फायदे गिनाए हैं। साथ ही कई बार की बातचीत के बावजूद सहमति नहीं बनने का सारांश दोष किसान संगठनों के सिर पर थोपा गया है। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के इस रवैये से जाहिर है कि उन्हें अब भी सारी कमी किसानों में ही नजर आ रही है और अपने मनमाने कानूनों को सही ठहराने की प्रबल इच्छा को वे महज चुनावों के चलते ढंप रहे हैं। ऐसे में यह संदेह होना स्वाभाविक है कि यही कानून किसी और नाम और शब्द में फिर से देश पर थोपे जा सकते हैं। जैसे कई बार तूफान के शांत होने का इंतजार मल्लाह करते हैं और फिर मछली पकड़ने के लिए अपना जाल फेंकते हैं, कुछ वैसा ही हाल चुनावों के बाद देश में देखने मिल सकता है। इसलिए अभी किसान अपनी बाकी मागों के साथ आंदोलन जारी रखे हुए हैं, तो यह लोकतंत्र के हित में ही है। सोमवार को संसद में कृषि कानून निरस्त कराने से पहले विषयक ने व्यापक चर्चा की मांग रखी थी। क्योंकि कानून वापसी के साथ-साथ लखीमपुर खीरी घटना और बिजली बिल सहित आंदोलन के दौरान हुई कई घटनाओं पर चर्चा विषय क्षात्र हता था। जबकि सरकार जानती थी कि अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। इसलिए उसने जिस तरह अपने बहुमत से कानून पारित करवाए थे, उसी बहुमत के घंटे में उन्हें बिना चर्चा के निरस्त भी करवा दिए। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है और ऐसे कई काले दिन पिछले सात सालों में देश ने देखे हैं। सोमवार को जब कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश हुआ तो इसके फौरन बाद कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने विधेयक पर चर्चा कराने की मांग शुरू कर दी। हालांकि अध्यक्ष ने कहा कि सदन में व्यवस्था नहीं है। सरकार ऐसे ही लचर तरकी से लोकतंत्र का मजाक बना रही है। अगर विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं तो सरकार को उस हंगामे के कारण को समझकर उसका निवारण करना चाहिए। सदन में चर्चा के लिए माहाल और व्यवस्था दोनों बनाना चाहिए। मगर अभी ऐसा लगता है कि सरकार भी हंगामे की आड़ में चर्चा से भागना चाहती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सही कहा है कि जिस प्रकार से इन कानूनों को रद्द किया है, बिना किसी बातचीत के वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "चर्चा नहीं होने दी- एमएसपी पर, शहीदों अन्नदाता के लिए न्याय पर, लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री की बखार्स्तगी पर उन्होंने कहा, "जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार, फेल है, डरपोक है वो सरकार। अब देखना होगा कि अपनी बहादुरी साबित करने के लिए सरकार आगामी दिनों में चर्चा का सामना करती है या फिर जनता से और विषय से भागी-भागी फिरती है।

विधानसभा चुनाव में समर्थन आधार बढ़ाने के लिए बोली

प्रदीपकपूर

भाजपा ने भी हिस्सेदारी मोर्चा से जुड़ी छह अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दिया, जो छोटे दलों का गठबंधन था जो अपने समुदायों को आवाज देने के लिए एक साथ आए थे। इन समुदायों में बिंद, गढ़रियाँ कुम्हार, धीवर, कश्यप और राजभर सहित औबीसी समूह शामिल हैं। गठबंधन के संयोजक हिस्सेदारी मोर्चा केवट रामाधीन बिंद कहा कि उन्हें पता चला कि भाजपा गैर-यादव पिछड़ों और दलितों पर काम कर रही है, इसलिए उन्होंने गठबंधन के लिए वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया। यह मोर्चा विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कम से कम 15 सीटों की उम्मीद कर रहा है। हिस्सेदारी मोर्चा की पार्टियाँ हैं - भारतीय मानव समाज पार्टी, शोषित समाज पार्टी, भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी, भारतीय समता समाज पार्टी, मानवहित पार्टी पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी और मुसहर आंदोलन मंच।

दूसरी ओर, प्रमुख विपक्षी दल और मुख्य चुनौती देने वाले अखिलेश यादव भी छोटी पार्टियों और विभिन्न जाति समूहों के साथ गठबंधन कर रहे हैं ताकि उनकी समाजवादी पार्टी मतदाताओं के बड़े समूह तक पहुंच सके। अखिलेश यादव ने बार-बार घोषणा की कि वह किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पिछले दिनों कांग्रेस और बसपा वे साथ गठबंधन का उनका बुरा अनुभव रहा है। अखिलेश ने हाल ही रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात की और गठबंधन को अंतिम रूप दिया, जिसके पश्चातीयी यूपी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। अखिलेश ने 36 सीटें रालोद के लिए छोड़ने का फैसला किया है और इनमें से कुछ सपा उम्मीदवार रालोद के चुनाव चिपक पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले एक साल के दौरान किसान आंदोलन ने रालोद को जबरदस्त बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप जयंत चौधरी का जनसभाओं को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। जाट, मुस्लिम और अन-

क्रास लक्ष्य शहर

2021 में युनाइटेड नेशंस आगेनर्ड्जेशन की शिखर बैठक में 19 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था। यह पहली जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ। भारत में नीति आयोग द्वारा इसको अमली जामा पहनाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत में क्रियान्वयन हेतु राज्यों वे योजना आयोग को यह दायित्व दिया गया है जो राज्यों के जिला स्तर तक अपनी क्षमता अनुसार यह कार्य कर रहे हैं। देश में 2020 में कोरोना कोविड की पहली लहर तथा 2021 में दूसरी लहर के कारण सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में शिथिलता आई थी किंतु अब उन्हें लक्ष्यों के क्रियान्वयन में सक्रियता आ रही है।

3 जून 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने राज्यसभा सतत विकास कार्यक्रम की उपलब्धियों का तीसरा संस्करण जारी किया। इस संस्करण में पिछले सालों की भाँति केरल राज्य प्रथम स्थान पर हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, आन्ध्रप्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखण्ड तीसरे स्थान पर, सिक्किम चौथे और महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर रहे। इन राज्यों को 70 से अधिक अंक प्राप्त होने के कारण फ्रंट रनर श्रेणी के राज्यों में हैं। दूसरी ओर सबसे पिछड़ी पर्किं में बिहार पहले, झारखण्ड दूसरे, असम तीसरे, अरुणांचल, मेघालय, राजस्थान और उत्तरप्रदेश चौथे तथा छत्तीसगढ़, नागालैंड और ओडिशा पांचवें स्थान पर रहे। ये सभी पिछड़े राज्य परफॉर्मर श्रेणी के राज्य कहे ज सकते हैं। सतत विकास कार्यक्रम के नगरीय सूचकांक में प्राप्तांक वे आधार पर घटते क्रम से ये नगर हैं:- 1. शिमला 2. कोयम्बटूर 3. चंडीगढ़ 4. तिरुवनंतपुरम 5. कोच्चि 6. पणजी 7. पुणे 8. तिरुचिरापल्ली 9. अहमदाबाद 10. नागपुर 11. चेन्नई 12. सूरत 13. ऐजोल नगर मिजोरम 14. राज्य 14. बेंगलुरु 15. भोपाल 16. बडोदरा 17. शिलांग मेघालय 18. विशाखापट्टनम 19. नासिक 20. दिल्ली 21. रायपुर 22. हैदराबाद 23. लुधियाना 24. रांची 25. अमृतसर 26. इंदौर 27. मदुरई 28. औरंगाबाद 29. राजकोट 30. विजयवाड़ा 31. गंगटोक सिक्किम 32. अगरतला, त्रिपुरा 33. मुंबई 34. ग्वालियर 35. देहरादून 36. लखनऊ 37. जयपुर 38. कानपुर 39. श्रीनगर 40. जबलपुर 41. गाजियाबाद 42. प्रयागराज 43. इम्फाल, मणिपुर

पिछड़ों का गठजोड़ भाजपा को टक्कर देने के लिए एक शक्तिशाली समूह बनाएगा। अखिलेश यादव ने शक्तिशाली राजभर नेता ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दिया, जिसका पूर्वी यूपी में बहुत प्रभाव है। 2017 की विधानसभा में भाजपा के साथ चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पिछड़ी जातियों की अनदेखी के लिए योगी सरकार की बहुत आलोचना की थी। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी ने भाजपा उम्मीदवारों का विरोध किया और चुनावों के बाद उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन को अंतिम रूप देने के बाद, अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में एक संयुक्त जनसभा को संबोधित किया जहां गठबंधन की घोषणा की गई थी। गैरतरलब है कि जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) ने भी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। यह पार्टी सबसे पिछड़ी जाति के लोगों की है, जिनका पूर्वी यूपी में 15 से 20 सीटों पर प्रभाव है। पार्टी अध्यक्ष संजय चौहान ने प्रदेश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं की एक प्रभावशाली बैठक की, जिसमें अखिलेश यादव मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर बोलते हुए अखिलेश ने अब तक उपेक्षित अति पिछड़ा वर्ग के साथ सत्ता साझा करने का वादा किया। हाल ही में शक्तिशाली ठाकुर नेता और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह की समाजवादी पार्टी के स्थापक मुलायम सिंह यादव से उनके आवास पर हुई मुलाकात से काफी महत्व जुड़ा हुआ है। मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद, राजा भैया के नाम से जाने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह ने घोषणा की कि उनकी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक एक सम्मानजनक सीट बंटवारे के फामूलैं के आधार पर गठबंधन के लिए तैयार है। अखिलेश यादव के अपने अलग हुए चाचा शिवपाल यादव के साथ समझौता करने और उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करने की संभावना है, जिसके लिए कुछ सीटें भी छोड़ सकते हैं।

पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक जारी

डॉ. हनुमत यादव

नगरों में अधिकतम नागरिक सुविधाओं के सर्वेक्षण में शिमला न प्रथम, कोयम्बूरु ने द्वितीय और चंडीगढ़ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस सर्वेक्षण सतत विकास लक्ष्य के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण सुविधा प्राप्त करने वाले नगरों के बारे में भी जानकारी एकत्रित की गई है। सतत विकास लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकांश लक्ष्य की नागरिक सुविधा मात्र एक ही नगर तक सीमित रही। सतत विकास लक्ष्य का पहला लक्ष्य, नगर से गरीबी की समाप्त करके शून्य स्तर पर लाने में तमिलनाडु का कोयम्बूरु, दूसरे लक्ष्य खुखरी शून्य स्तर पर लाकर गरीबी से मुक्ति करल राज्य का कोच्चि, तीसरा लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली शिमला चौथा लक्ष्य गुणवत्तापरक शिक्षा केरल राज्य का तिरुवनंतपुरम, पांचवा लक्ष्य, लैंगिक समानता- में कोच्चि, छठवा लक्ष्य स्वच्छ जल एवं स्वच्छता- भोपाल नगर तक सीमित रही। विगत 18 नवंबर को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने पहला सतत विकास लक्ष्य नगरीय सूचकांक जारी करते हुए अपने वक्तव्य में कहा नीति आयोग और जीआईजेड के बीच अनूठी भागीदारी के जरिए तैयार एसडीजी शहरी सूचकांक है। राजीव कुमार ने कहा कि शहर तेजी से वृद्धि के इंजन बनते जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि नगरीय सूचकांक और डैशबोर्ड हमारे शहरों में एक मजबूत एसडीजी जनगणनी प्रणाली स्थापित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। नगरीय सूचकांक के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 56 क्षेत्रों में 44 बड़ी आबादी वाले बड़े नगर चुने गए हैं तथा 12 उत्तरपूर्व के राज्यों की राजधानियां चुनी गई हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी कम है। पहले सतत विकास लक्ष्य के नगरीय सूचकांक में सबसे अधिक नागरिक सुविधा संपन्न नगरों में पहले स्थान पर 75.50 प्राप्तांक के साथ शिमला, दूसरे स्थान पर 73.56 प्राप्तांक के साथ कोयम्बूरु तथा तीसरे स्थान पर 72.56 प्राप्तांक के साथ चंडीगढ़ पाया गया। 65 से 99 अंक प्राप्त करने वाले नगरों को 'फ्रंट रनर नाम दिया गया है। इन तीन नगरों के बाद चौथे से दसवें स्थान पर क्रमशः तिरुवनंतपुरम प्राप्तांक 72.36, कोच्चि प्राप्तांक 72.29, पणजी प्राप्तांक 71.80, पुणे प्राप्तांक 71.21, तिरुचिरापल्ली प्राप्तांक 70.00, अहमदाबाद प्राप्तांक 69.79 और नागपुर प्राप्तांक 69.70 नगर हैं।

अंक प्राप्त करने वाले नगर 'प्रोफॉर्म श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। 56 नगरों में सबसे कम नागरिक सुविधा संपन्न 10 नगरों में सबसे निचले स्थान पर धनबाद है जिसके प्राप्तांक 52.43 है। नीचे से दूसरे स्थान पर मेरठ प्राप्तांक 54.64 तथा तीसरे स्थान पर गुवाहाटी प्राप्तांक 55.79 है। नागरिक सुविधा में निचले 10 नगरों में क्रमशः पटना प्राप्तांक 57.29, जोधपुर प्राप्तांक 58.00, कोहिमा प्राप्तांक 58.07, आगरा प्राप्तांक 58.21, कोलकाता 59.50 और फरीदबाद 58.57 है। यहां पर प्राप्तांक निर्धारण नियमों एवं स्कीम निर्धारक के बारे में बता देना जरूरी है। प्राप्तांक निर्धारण हेतु 46 टारगेट तय किए गए हैं और मूल्यांकन के लिए 77 सूचक हैं। नीति आयोग ने 'इंडो-जर्मन डेवलोपमेंट कॉऑपरेशन' के तहत जीआईजे और बीएमजे द्वारा साथ मिलकर नगरीय सूचकांक और ताजा जानकारी के लिए 'डेशबोर्ड विकसित किया है। सतत विकास लक्ष्य और इनके 169 उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एंडोंडा है जिसे सितम्बर

3 44. भुवनेश्वर, 45. कोटा, 46. वाराणसी, 47. फरीदाबाद, 48.
 मे कोलकाता, 49. आगरा, 50. कोहिमा, नागालैंड राज्य 51. जोधपुर
 र 52. पटना, 53. गुवाहाटी, 54. इटानगर अस्सिंचल राज्य, 55.
 5 मेरठ 56. धनबाद झारखण्ड राज्य ।

यह बताया जा चुका है कि नगरों में अधिकतम नागरिक सुविधाओं के सर्वेक्षण में शिमला ने प्रथम, कोयम्बूर ने द्वितीय और चंडीगढ़ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस सर्वेक्षण सतत विकास लक्ष्य के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण सुविधा प्राप्त करने वाले नगरों के बारे में भी जानकारी एकत्रित की गई है। सतत विकास लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकांश लक्ष्य की नागरिक सुविधा मात्र एक ही नगर तक सीमित रही। सतत विकास लक्ष्य का पहला लक्ष्य, नगर से गरीबी की समाप्त करके शून्य स्तर पर लाने में तमिलनाडु का कोयम्बूर, दूसरे लक्ष्य भुखमरी शून्य स्तर पर लाकर गरीबी से मुक्ति करल राज्य का कोच्चि, तीसरा लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली शिमला चौथा लक्ष्य गुणवत्तापरक शिक्षा करल राज्य का तिरुवनंतपुरम, पांचवा लक्ष्य, लैंगिक समानता- में कोच्चि, छठवा लक्ष्य स्वच्छ जल एवं स्वच्छता- भोपाल नगर तक सीमित रही। सतत विकास कार्यक्रम का सातवां लक्ष्य: सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा: शिमला, आठवां लक्ष्य सराहनीय कार्य एवं आर्थिक विकास- बैंगलुरु, नौवां लक्ष्य उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, सूरत गुजरात, दसवां लक्ष्य असमानताओं में कपी- अमृतसर, ग्यारहवा लक्ष्य- सवंहीन शहर एवं समुदाय, नासिक, चौदहवां लक्ष्य जलीय जीवों की सुरक्षा, पद्धतवां लक्ष्य थलीय जीवों की सुरक्षा बारहवां लक्ष्य, संवर्हनीय उपभोग एवं उत्पादन:आगरा, अहमदाबाद, बैंगलुरु, फरीदाबाद हरियाणा, गाजियाबाद, गुवाहाटी, ग्वालियर, कानपुर, पटना, प्रयागराज, राजकोट, शिमला, वाराणसी, तेरहवां लक्ष्य: जलवायु कार्रवाई: एजवल, कोच्चि, शिलांग, शिमला और तिरुवनंतपुरम, तथा सोलहवां लक्ष्य शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थाएं, पणजी रहा। लक्ष्य हेतु भागीदारी सत्रहवां लक्ष्य, रहा। नवम्बर 2022 में दूसरा सतत विकास लक्ष्य नगरीय सूचकांक जारी किए जाने की संभावना है। चूकि स्थिति अब सामान्य होती जा रही है इसलिए अगले 2022 में नगरीय सूचकांक के हर एक क्षेत्र में प्रगति होने की पूरी संभावना है।

भू-सीमा गतिविधियों पर चैन के नए कानून के भारत के लिए गंभीर निहितार्थ

कानून कहता है कि राज्य सीमा रक्षा को मजबूत करने, आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में खुलने, ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार करने, लोगों वे जीवन को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने और वहां काम करने वे लिए उपाय करेगा, और बढ़ावा देगा। चीनी समाचार एजेंसी सिन्हुआ बताया कि सीमा रक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक विकास के बीच समन्वय के लिए ऐसा किया जा रहा है। २०२२ में भारत चीन वे साथ लगी अपनी वास्तविक सीमा पर गंभीर घुसपैठ और घटनाओं का आशंका कर सकता है। चीनियों ने अभी-अभी एकतरफा एक नया कानून

अंजन राय

पारित किया है जो चीनी राज्य को अपनी भूमि सीमाओं के साथ कई तरह की गतिविधियां करने का अधिकार देता है, जिसका संक्षेप में मरलब है कि चीन बसने वालों को सीमावर्ती क्षेत्रों में बसा सकता है। भारत ने इस एकत्रफा कदम का औपचारिक रूप से विरोध किया है। कानून कहता है कि राज्य सीमा रक्षा को मजबूत करने, आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में खुलने, ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार करने, लोगों के जीवन को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने और वहां काम करने के लिए उपाय करेगा, और बढ़ावा देगा। चीनी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि सीमा रक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक विकास के बीच समन्वय के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये बसियां उन सभी विवादित क्षेत्रों में भी स्थापित की जा सकती हैं जहां चीन के पड़ोसी देशों के साथ मौजूदा समझौते नहीं हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच की पूरी सीमा वस्तुतः विवादित बनी हुई है और द्विपक्षीय रूप से स्वीकृत सीमांकन रेखाएं खींची जानी बाकी हैं। इसलिए कानून उन सभी कार्यों के लिए द्वारा खोलता है कि जिन्हें चीनी अधिकारी उद्देश्यों और गतिविधियों के व्यापक दायरे के लिए उपयुक्त समझते हैं। इस तरह के एकत्रफा प्रावधान सभी स्वीकृत राजनीय प्रथाओं का उल्लंघन में है और एक उत्तेजक कार्रवाई है। भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्र भूमि की प्रकृति के कारण दुर्गम और कम आबादी वाले हैं। चीनी नीतियां हान आबादी वाले केंद्रीय क्षेत्रों से लोगों को लाने और उन्हें उन क्षेत्रों में फिर से बसाने की हैं जिन पर वे मजबूती से नियंत्रण करना चाहते हैं। वे डिजिटांग में इस रणनीति का पालन कर रहे हैं, जहां बहुसंख्यक उड़गर आबादी को अल्पसंख्यक बना दिया जा रहा है। नया कानून पिछ्ले शनिवार को पारित किया गया था और भारत ने कानून के प्रावधानों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, इस डर से कि इन उद्देश्यों का पीछा करने से भारत-चीन सीमा क्षेत्र पूरी तरह से बदल सकते हैं और एलासी को परेशान कर सकते हैं। चीन पड़ोसी देशों के साथ अपने व्यवहार में तेजी से आक्रामक रुख अपना रहा है। यह युद्ध के लगातार परिष्कृत और शक्तिशाली हथियारों के अधिग्रहण के साथ, अपनी रक्षा क्षमताओं के बारे में एक नया आत्मविश्वास महसूस कर रहा है और व्यक्त भी कर रहा है। अभी हाल ही में, चीन ने कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों और ग्लाइड वाहनों का परीक्षण किया है ताकि परमाणु हथियारों से लैस शस्त्रांगार ले जाया जा सकें। ये वास्तव में बेहद शक्तिशाली हथियार हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने के लिए नियरानी रडार प्राप्त कर सकते हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल वाहन अमेरिकी मिसाइल ढालों को भी भेद सकते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी मासपेशियों के लचीलेपन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एक सर्वोच्च रैंकिंग अमेरिकी सैनिक ने इस घटना को चीन के लिए स्पृतनिक प्लस के रूप में वर्णित किया है।

जीते हारे कोई : अजेंडा तो बन गया गरीब, दलित, किसान

शकील अख्तर

शकील अख्तर

हाथरस से लेकर जितने भी कांड हुए उसके बाद पीड़ित परिवार को ही और परेशान करने के मामले ही सामने आए। प्रियंका हर जगह पहुंची। और जैसा कि अभी प्रयागराज के मामले में देखा कि उसके बाद अखिलेश और मायावती को ट्वीट करना पड़ा। आप के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी किया। केवल ट्वीट। और वह भी इसलिए कि प्रियंका वहां गई। प्रियंका ने पीड़ितों के साथ खड़ा होकर हिम्मत का माहौल बना दिया। उन्हें कई बार पुलिस के द्वारा रोका गया। सोनभद्र और लखीमपुर जाते हुए हिरासत में लिया गया। मगर वे पीड़ित परिवारों से मिले बिना वापस आने को तैयार ही नहीं हुईं। मजबूर होकर उन्हें जाने दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी नम्बर एक से लेकर तीन तक की भाजपा, सपा, बसपा कोई पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने को वहां नहीं गया। मगर इसके बावजूद वे अब इन घटनाओं को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं रहे। प्रियंका ने गरीब का, दलित का, किसान का महिलाओं का अजेंडा सेट कर दिया है। अब हर पार्टी को चाहे वह सत्ता पक्ष हो या मुख्य विपक्षी दल पीड़ितों की बात करना पड़ रही है। मायावती और अखिलेश चाहे जाएं नहीं मगर ट्वीट के जरिए ही उन्हें अपना समर्थन देना पड़ रहा है और भाजपा की सरकार को चाहे वह जाति के आधार पर किसी को कम, किसी को ज्यादा मुआवजा दे मगर देना पड़ रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत मीडिया की है प्रियंका के वहां जाने के बाद वह घटना को छूपा नहीं पाती है। चाहे कम दे, चाहे अपराधियों का समर्थन करते हुए दे मगर खबर देना पड़ रही है। यही प्रियंका की सफलता है। यही वह न्याय का, कानून व्यवस्था का, गरीब पर जुल्म का, महिला सुरक्षा का, किसान का, और आम जनता का अजेंडा है जो प्रियंका सेट करना चाह रही हैं। चुनाव के नतीजे चाहे जो हों मगर जनता के वास्तविक सवाल इस दौरान उठना चाहिए और बांटे वाले सवाल जनता से दूर होना चाहिए। प्रियंका

देश/विदेश संदेश

तीन दिन में दूसरी बार भाजपा ने सपा-बसपा को दिया झटका

पूर्व विधायक जगपाल सिंह समेत कई नेता पार्टी में शामिल

लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे-सैसे नेताओं का पाला बदल देज हो रहा है। भाजपा ने मंगलवार को एक बार फिर सपा-बसपा को झटका देते हुए कई नेताओं को पार्टी में शामिल किया है। इसे सबसे बड़ा नाम चार के पूर्व विधायक बसपा ने तो जगपाल सिंह का नाम शामिल है। भाजपा ने पूर्वचाल से लेकर पश्चिमी यूपी तक के कई नेताओं को पार्टी में शामिल किया है। पूर्वचाल के बलिया, मऊ, गाजियापुर से लगभग एक दर्जन नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। आठ बीएसपी नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। पूर्व विधायक जगपाल सिंह के अलावा बलिया के बसपा नेता छद्दु प्रसाद, अंजय चूमार, वेरिया के अमेश कुमार सिंह, सपा नेता राम दिनेश प्रताप सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले रविवार को सपा सकारा में मंत्री रहे गाजियापुर के पूर्व मंत्री विजय मिश्रा साहूत कई

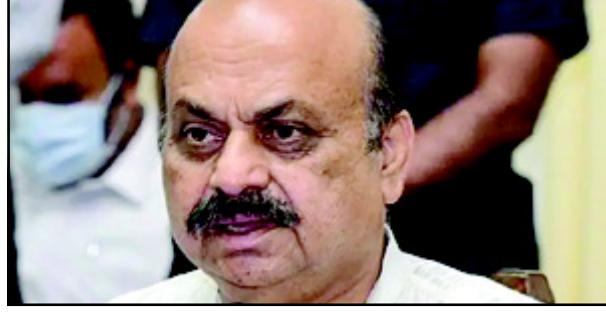


नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था। जो लोग भाजपा में शामिल हुए उनमें पूर्व मंत्री जय नारायण तिवारी सुलतानपुर सपा से, मणिज दिवाकर बसपा नेता कानपुर से, जगदेव बसपा के पूर्व वित्ताध्यक्ष, अशोक कुमार सिंह पूर्व आईएस, बीएसपी के अमेश कुमार सिंह, सपा नेता राम दिनेश प्रताप सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले रविवार को सपा सकारा में मंत्री रहे गाजियापुर के पूर्व मंत्री विजय मिश्रा साहूत कई

राम शिरोमणि शुक्ला कांग्रेस के पूर्व विधायक, धर्मेंद्र पांडे उनाव से बसपा नेता, मदन गौतम पूर्व विधायक औरेया से बसपा से, कुवर अभिमन्तु, सिंह अयोध्या से समाजसेवी शामिल हुए थे। बसपा का गढ़ कहे जाने वाले

जनपद सहारनपुर में बसपा को छाके पर झटके लग रहे हैं। हौड़ा (उन्नाम में सहारनपुर देहात) से तीन बार विधायक चुने गए जगपाल सिंह भाजपा में शामिल हो गए। हौड़ा विधानसभा सीट से वर्ष 1997 में हुए चुनाव में जगपाल सिंह मामूली अतर से कांग्रेस के मस्त अंजार से चुनाव हार गए। इसके बाद से जिले में बसपा में समाज-उथल-युक्त प्रभावी है लेकिन पुलिस सतर्क हो गई है। बीएसपी जाकारी के अनुसार, अभिनवी जगना रनौत को मिल रही जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज किया केस शिल्मा। फिल्म अभिनवी जगना सौते ने लगातार मिल रही धमकीयों पर हिंसात्मक प्रेस पुलिस के शिकायत दर्ज की है। अपनी शिकायत में जगना को कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक गुरुदेव सूर्य ने कहा कि अभिनवी को हालांकां वाई-प्लस श्रेणी की सुखा मिली हुई है लेकिन पुलिस सतर्क हो गई है। मिली जाकारी के अनुसार, अभिनवी जगना रनौत ने बुधवार सुबह ईस्टरग्राम पोस्ट में बताया है कि उन्होंने एक पोस्ट सुर्खेत अंतर्नी हमले शहीदों को घायल करते हुए लिखी थी, जिसके बाद उन्हें बिठाड़ा के किसी व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। कंगाना ने वर्ष 2003 में अपने परिजनों के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए पोस्ट में कहा, "मैं एक पोस्ट में लिखा था कि गद्दारों को कभी माफ नहीं करना अब न ही भूलना।

वो कोविड गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करें उन्होंने कहा कि जहां पर नए वैरिएंट के मामले



सामने आए हैं उन देशों से राज्य में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की एपरिपोर्ट पर ही टेस्ट की जा रही है। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्हई ने कहा कि हमने स्कूलों और कॉलेजों में सख्त सावधानी बरने का निर्देश दिया है कि उन्हें बढ़ करने को कहा है। लाकडाउन का कोई प्रताप नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओमिक्रोन के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से अपील की कि

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के बाद दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। सीमा बोम्हई ने कहा कि कर्नाटक सरकार विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही है।

के ब